*एनआईबीएम स्वर्णजयंती समारोह**

- महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी
- गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री शक्तिकांत दास
- निदेशक, राष्ट्रीय बैक प्रबंधन संस्थान, डॉ. के एल ढींगरा
- प्रबंध मंडल के सदस्य , छात्र, संकाय और अन्य स्टाफ सदस्य
- विशिष्ट अतिथिगण
- देवियो और सज्जनो

राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) के स्वर्ण जयंती समारोह पर आप सभी के साथ रहने की मुझे असीम खुशी है। राष्ट्र के लिए पचास साल की सेवा गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर संस्थान से जुड़े हर व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूं।

क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों की महान दूरदर्शिता थी। यह स्वायत्त सर्वोच्च संस्थान के रूप में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और बैंक प्रबंधन में परामर्श के लिए स्थापित किया गया था। यह अपने अधिदेश पर खरा उतरा है मुझे पता चला है कि स्थापना के बाद से यहां 1.1 लाख से अधिक बैंकरों को प्रशिक्षित किया गया है। एनआईबीएम परिसर ने लगभग 9,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अतिथ्य किया है। इस प्रकार संस्थान ने भारत की 'सॉफ्ट पावर' के निर्माण में विदेशों में बहुत योगदान दिया है। राष्ट्रपति के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, भारत के युवाओं के साथ-साथ भारत में शिक्षित या प्रशिक्षित उन युवाओं को देखकर मुझे खुशी हो रही है जिन्होंने छाप छोडी हैं।

देवियो और सज्जनो,

बैंक हमारी आर्थिक प्रणाली के आधार हैं। इस भूमिका में उनकी दक्षता ने लोगों का विश्वास और सम्मान जीत लिया है। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय का वादा किया। इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बैंकों को महत्वपूर्ण उत्प्रेरक माना गया। इस अवसर पर, एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से परे एक अधिदेश का अच्छी तरह अनुसरण करने के लिए मैं भारत के बैंकों की सराहना करता हूं। वे हमारी आबादी के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए राज्य के प्रयासों का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

इन वर्षों में, बैंकों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आजादी के समय, बैंकिंग क्षेत्र को उपस्थिति की कमी और अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नवजात गणतंत्र के लिए, अपने नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर बनाने में ये बड़ी बाधाएँ थीं। तब से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति संतोषजनक है। आज एक वर्ष में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या आजादी के समय की कुल शाखाओं की संख्या के बराबर है। भारत के अधिकांश गाँवों में बैंकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक निगरानी ने भी बैंकिंग परिचालन में अधिक स्थिरता लायी है। मुझे पता चला है कि हाल ही में विनियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका को मजबूत किया गया है। हमें विश्वास है कि यह कुप्रथाओं को दूर करेगा और हमारी वित्तीय प्रणालियों को और विश्वसनीय बनाएगा।

आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक, बड़ी संख्या में लोगों, विशेष रूप से गरीबों के लिए, बैंकिंग तक कोई पहुंच नहीं थी। “प्रधानमंत्री जन धन योजना” के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों ने इस स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। कोई यह कह सकता है कि इतिहास में पहले कभी भी इतने लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में नहीं लाया गया है। जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ी, लगभग 35 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। यह संख्या हमारे और चीन के अलावा सभी देशों की जनसंख्या से बड़ी है।

* माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे, के स्वर्णजयंती समारोह में दिया गया संबोधन ।

मैं इसे संभव बनाने में बैंकिंग क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के प्रयासों की दिल से सराहना करता हूं। मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि किसी भी नागरिक को पीछे न छोड़ें। बैंकर को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह 'मार्केट डेप्थ' और 'डी-रिस्किंग ऑपरेशंस' हासिल करने का एक और उत्तम उपाय है।

वित्तीय समावेशन के माध्यम से, हमने अपनी जनसंख्या के बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्रों को समावेश करने में तेजी से प्रगति की है। हमारे सामने अब शामिल लोगों को और अधिक तीव्रता से शामिल करने की चुनौती है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय उत्पादों के बारे में सोचे। मैंने देखा है कि एनआईबीएम में अच्छी अनुसंधान सुविधाएं हैं। इनका उपयोग आबादी के गरीब वर्गों के लिए वित्तीय उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। देश की प्रगति गरीबों की सामूहिक आर्थिक ताकत के योगदान पर निर्भर करती है। महिलाओं की अगुवाई में स्वयं सहायता समूह के आंदोलनों ने यह दिखाया कि गरीबों में निवेश करने से लाभ मिल सकता है।

सामाजिक व्यवस्था के हाशिए पर रहने वाले लोगों की सहभागिता के लिए बैंकर्स द्वारा सहानुभूति और अनुकंपा प्रकट करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी कम सेवा वाले बैंकों के क्षेत्र में अधिक से अधिक जुड़ाव और उनके प्रति नजरिए में बदलाव की जरूरत है। हमारे बैंकों ने आम आदमी के लिए सेवा उपलब्ध कराके अभिजात्य वर्ग से बैंकिंग को बदलने में एक सराहनीय काम किया है। गरीबों और जरूरतमंदों के बैंक खाते में, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाखों लोगों को प्रत्यक्ष निधि अंतरण का लाभ मिला है। मुझे पता चला है कि यह राशि लगभग 9.2 लाख करोड़ रुपये है। यह वास्तव में बहुत ही आश्वस्त करने वाला है और हम अपनी उम्मीदों के स्तर को बढ़ा सकते हैं।

आप सभी सहमत होंगे कि महिलाओं में अधिक वित्तीय कौशल है। मैं इस बात पर संतोष व्यक्त करता हूं कि खाताधारकों में लिंग भेद तेजी से कम हो रहा है। यह हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय के हमारे संवैधानिक लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं बैंकों से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय आस्तियों में अधिक से अधिक लिंग समानता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में बैंक, महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को अपना सकते हैं। एनआईबीएम टूलकिट डिजाइनिंग पर विचार कर सकता है, जो बैंक उपयोग कर सकते हैं।

भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी यात्राओं के दौरान मुझे कई 'दिव्यांग'व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला। उनके साथ मेरी बातचीत से, सक्षम वातावरण दिए जाने पर उनकी जबरदस्त क्षमता का पता लगा। हमारी आबादी में 2 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं और हमें वित्तीय मुख्यधारा में उन्हें पूरी तरह से एकीकृत करने का हर संभव प्रयास करना होगा। मुझे पता चला है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिव्यांगजनों 'की बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुँच के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह करूंगा कि हमारी 'दिव्यांगजन' बहनों और भाइयों 'को वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सभी उपाय करें।

देवियो और सज्जनो,

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। बैंक भारत की विकास गाथा का निरंतर हिस्सा रहे हैं। जैसा कि भारत का लक्ष्य 5-ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, बैंकिंग क्षेत्र को अगली बड़ी छलांग के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से "बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्र में बैंकिंग" और "असुरक्षित को सुरक्षित करना" शामिल है। इस खोज में, वैश्विक मानकों के बैंकिंग संस्थानों की सेवा करने के लिए कुशल प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक पूल बनाने की जिम्मेदारी लेने का एनआईबीएम से मैं आग्रह करता हूं।

यदि बैंक गहरी पहुँच प्रदर्शित करते हैं और अधिक कुशल बनते हैं तो भारत की भविष्य की यात्रा में बहुत सहायक होगा। हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार को देखते हुए, हमें दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में एक से अधिक नाम रखने का लक्ष्य रखना चाहिए।

हमारे भविष्य के रोडमैप पर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' पर भी विचार करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह लाभ उचित रूप से प्राप्त किया जाए। मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं आकांक्षात्मक उद्यमियों को धन मुहैया करा रही हैं। मैं सभी बैंकरों से निवेदन करूंगा कि वे गहरी नजर रखें और धन की कमी के लिए अच्छी योजनाओं को नष्ट न होने दें।

तकनीकी को अपनाने में बैंक सबसे आगे रहे हैं। तेज निपटान प्रणाली, इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान बैंकों जैसे नवाचारों ने ग्राहक

के लिए बैंकिंग को बहुत आसान बना दिया है। वैश्विक प्रशंसा जो कि स्वदेशी रूप से विकसित यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने खींची है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया एक उपहार है और सभी भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं।। मुझे विश्वास है कि उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए बैंक नई उभरती हुई तकनीकों को देख रहे हैं। मुझे भरोसा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक मार्गदर्शन भी दे रहा है, साथ ही प्रौद्योगिकी को अपनाने में उचित सुरक्षा उपायों के मुद्दे को भी संबोधित कर रहा है।

देवियो और सज्जनो,

स्वतंत्रता के बाद बैंकों को इक्विटी के साथ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक करार का हिस्सा माना जाता था। देश की आर्थिक प्रणाली में बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। हमारे राष्ट्र के संस्थापक इस बात के प्रति बहुत सचेत थे कि बैंकों को सार्वजनिक न्यास के धारक के रूप में भूमिका निभानी होगी। मैं सभी बैंकरों को इस कसौटी पर अपने कार्यों को परखने के लिए प्रेरित करूंगा। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में, अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव विवेकपूर्ण उपाय करने होंगे कि किसी भी तरह से विश्वासघात न हो। हाल ही में निक्षेप बीमा कवरेज को ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख करने का प्रस्ताव बचतकर्ताओं को आश्वासन देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

छोटी शुरुआत से, बैंक बहुसांस्कृतिक संगठन बन गए हैं। इसलिए, बैंक हमारे संविधान में निहित अधिकता के मूल्यों के लिए खड़े हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बैंकों के भीतर समानता और विविधता के साथ-साथ समाज के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करना जारी रखें।

यह प्रशंसनीय है कि एनआईबीएम को भारत और विदेशों में अध्ययन और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुझे पता चला है कि एनआईबीएम हमारे बैंकिंग क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए जनशक्ति विकसित कर रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वर्तमान और अतीत के निदेशकों, संकाय और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और बैंकिंग उद्योग का समर्थन करने के लिए उनके अधिक समर्पण और योगदान की आशा करता हूं।

मैं एनआईबीएम के छात्रों और संकाय सदस्यों को उनके भविष्य के प्रयासों और आगे के कई शानदार वर्षों में सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।